केन-बेतवा परियोजना को केंद्र की मंजूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : बुंदेलखंड में घर-घर पानी और खेत-खेत पानी पहुंचाने वाली बहुप्रतीक्षित केन व बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई। आठ वर्षों में पूरी होने वाली इस परियोजना पर तकरीबन 45 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस परियोजना से जहां बुंदेलखंड के 10.5 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे में सिंचाई की सुविधा मिलने लगेगी, वहीं 62 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले बुंदेलखंड की सूखी धरती में पानी समाने से भूजल का स्तर भी ऊपर आएगा।

पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना से 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) नामक विशेष प्रयोजन संस्था का गठन भी किया जाएगा। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना व टीकमगढ़ और उप्र के बांदा, महोबा, हमीरपुर और झांसी समेत अन्य जिलों के प्रायः सूखाग्रस्त और पानी की कमी वाले जिलों में कुल 10.62 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इन जिलों के 62 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए इन्हें नहरों से जोड़ा जाएगा।

शेष >> पेज 17

तोहफा

- 45 हजार करोड़ की है परियोजना, बुंदेलखंड को मिलेगा लाभ
- 10.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई, 62 लाख लोगों को मिलेगा पेयजल
- 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का भी उत्पादन

पेज एक का शेष

केन-बेतवा परियोजना...

ठाकुर ने बताया कि परियोजना अन्य नदियों को जोड़ने की प्रस्तावित परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसके तहत केन का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। परियोजना को लेकर पहला विचार पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी का था। उन्होंने नदियों के बेकार हो रहे जल के सदुपयोग के लिए सूखी नदियों से जोड़ने की योजना के बारे में प्रस्ताव तैयार करने को कहा था। राज्यों के बीच सहमति बनाने में लंबा समय लगा। अंततः 22 मार्च 2021 को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की पहल से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।